Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 12, Issue 2 | November 2024 - April 2025 | pp. 113-117

विकसित भारत 2047 में शिक्षा एवं शिक्षकों की भूमिका

डॉ. ईश्वरचन्द्र शर्मा

सह आचार्य, राजनीति विज्ञान
राजकीय कन्या महाविद्यालय, मगरापुंजला, जोधपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प व्यक्त किया है। इस हेतु सभी क्षेत्रों में विकास एवं सभी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की भागीदारी आवश्यक है। इन सभी क्षेत्रों में विकास के लिए शिक्षा एवं शिक्षकों की भूमिका अतिमहत्वपूर्ण है। विकसित भारत तभी होगा जब आम आदमी की आमदनी में वृद्धि होगी अर्थात् उसकी आय अधिक होगी। देश में प्रौद्योगिकी और तकनीकी क्षेत्र में उन्नति नजर आने लगेगी एवं लोगों का जीवन स्तर उच्च तथा उन्नत होगा। बेरोजगारी और गरीबी की दर कम होगी एवं देश की जीडीपी का स्तर ऊँचा होगा। इन सभी विकसित भारत के तत्वों की प्राप्ति शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव है। शिक्षा मनुष्य को संस्कारित करती है। उनमें मूल्यों का विकास करती है। बालक में नागरिकता के गुणों को विकसित कर उसे एक सुनागरिक बनाती है। विद्यार्थी में छिपी प्रतिभा कला और कौशल को उद्घाटित करती है। शिक्षा नवाचार और इनोवेशन को बढ़ावा देती है। विकसित भारत में शिक्षा जहाँ एक ओर अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली होगी वहीं दूसरी ओर वह विद्यार्थियों में नैतिकता को भी बढ़ाएगी। प्रस्तुत अध्ययन ऐतिहासिक, तुलनात्मक एवं पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति के माध्यम से यह विश्लेषित करने का प्रयास करता कि विकसित भारत का अर्थ क्या है, उसके मुख्य तत्व क्या है और विकसित भारत की प्राप्ति हेतु शिक्षा और शिक्षकों की भूमिका क्या हो सकती है।

संकेताक्षर—*विकसित भारत, जीडीपी, प्रौद्योगिकी, नवाचार*

प्रस्तावना

विकसित भारत 2047 में शिक्षा एवं शिक्षकों की भूमिका को समझने हेतु सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम विकसित भारत कहेंगे किसे? या यूँ कहें कि भारत को विकसित बनने के लिए किन मानदण्डों को पूरा करना होगा? विकसित भारत तभी होगा जब आम आदमी की आमदनी में वृद्धि होगी अर्थात् उसकी आय अधिक होगी। देश में प्रौद्योगिकी और तकनीकी क्षेत्र में उन्नति नजर आने लगेगी एवं लोगों का जीवन स्तर उच्च तथा उन्नत होगा। बेरोजगारी और गरीबी की दर कम होगी एवं देश की जीडीपी का स्तर ऊँचा होगा। स्वतन्त्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत 2047 का जिक्र किया। लाल किले से देश के लिए सम्बोधन में उन्होंने कहा, भारत 2047 तक विकसित देश बन जाएगा।[1] जुलाई, 2024 में पेश हुए केन्द्रीय बजट में वितमंत्री निर्मला सीतारमण ने भी विकसित भारत को लक्ष्य बताया। "भारत को विकसित बनाने के लिए चार स्तम्भ युवा, गरीब, महिलाएँ और किसान बताए गए है।"[2]

विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिन बातों को महत्वपूर्ण माना गया है, उनमें प्रमुख है—आर्थिक विकास की दर में वृद्धि, सुरक्षित पर्यावरण, सामाजिक विकास और सुशासन। वितमंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत की जिन नौ (9) प्राथमिकताओं का उल्लेख किया है, वे इस प्रकार से हैं—(1) कृषि में उत्पादकता (2) रोजगार और कौशल विकास (3) समावेशी मानव संसाधन विकास और

सामाजिक न्याय (4) विनिर्माण और सेवाएँ (5) शहरी विकास (6) ऊर्जा सुरक्षा (एनर्जी सिक्योरिटी) (7) बुनियादी ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) (8) इनोवेशन रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट (9) नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म।

विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिन बातों पर बल दिया है, उनमें प्रमुख हैं—देश को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाना, तकनीक में आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हुए मैन्युफैक्चरिंग में लीडर बनाना, युवाओं में कौशल विकास को बढ़ाते हुए, भारत को दुनिया की स्किल कैपिटल बनाने पर जोर देना, मेक इन इंडिया के प्रभाव से नौकरियों की संख्या में बढ़ोतरी, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश (सोलर पॉवर और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर काम करना), प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन और ग्रोथ पर धान देना और गरीबी और गुलामी से आजादी दिलाना। नरेन्द्र मोदी के शब्दों में "विकसित भारत 2047 नई आजादी दिलाने जैसा होगा। यह गरीबी और गुलामी की मानसिकता से मिलने वाली आजादी होगी।"

शिक्षा एवं शिक्षकों की भूमिका

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की पूर्ति हेतु निर्धारित मानदण्ड हो या वितमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बताई गई विकसित भारत की नौ प्राथमिकताएँ अथवा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए बताई गई बातें, इन सभी की प्राप्ति हेतु शिक्षा और शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनुष्य को संस्कारित करती है। उनमें मूल्यों का विकास करती है। बालक में नागरिकता के गुणों को विकसित कर उसे एक सुनागरिक बनाती है। विद्यार्थी में छिपी प्रतिभा कला और कौशल को उद्घाटित करती है। शिक्षा नवाचार और इनोवेशन को बढ़ावा देती है। विकसित भारत में शिक्षा जहाँ एक ओर अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली होगी वहीं दूसरी ओर वह विद्यार्थियों में नैतिकता को भी बढ़ाएगी।

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में नई शिक्षा नीति 2020 (एन.ई.पी) की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इस सन्दर्भ में भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनकड़ का कहना है कि "विकसित भारत अब सपना नहीं हैं, विकसित भारत लक्ष्य है और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है और यह लक्ष्य हम हासिल करके रहेंगे, यह हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी सोच को दर्शाते हुए तीन दशक के बाद, लाखों लोगो की राय लेने के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया है। मैं अपील करूँगा, जिन प्रान्तों ने इसको अडॉप्ट नहीं किया है, वह अडॉप्ट करें। मैं यह भी सन्देश देना चाहूँगा की हर संस्था का प्रिंसीपल, डायरेक्टर, वाईस चांसलर नीति का अध्ययन करें, क्योंकि नीति बहुत दूर-दर्शिता प्रदर्शित करती है।"[3]

जी.बी. पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद के निदेशक प्रो. बद्रीनारायण तिवारी के शब्दों में "शिक्षा का यह नया मॉडल विद्यार्थियों को विषय चयन करने की स्वतन्त्रता देता है, जिससे वे अपनी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार सीख सके। यह लचीलापन न केवल उनकी शैक्षणिक यात्रा को सुगम बनाता है। बल्कि उन्हें बहुक्षेत्रीय दक्षताओं से लैस करेगा। अंतर विषयी शिक्षा का यह दृष्टिकोण भारत में पहली बार एक बड़े स्तर पर लागू किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को जड़ों से जोड़ना है। भारतीय परम्पराओं, संस्कृति और मूल्य, शिक्षा के अभिन्न हिस्सा होंगे, जिससे विद्यार्थियों में अपने समाज और इतिहास के प्रति जागरुकता बढ़ेगी। साथ ही वैश्विक दृष्टिकोण और तकनीकी नवाचारों को भी शिक्षा में समाहित किया जा रहा है। इसका परिणाम यह होगा कि छात्र न केवल भारत में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रभावशाली भूमिका निभाने में सक्षम होंगे। भारत की शिक्षा व्यवस्था का यह परिवर्तन देश की प्रगति का आधार बनेगा। एक ऐसा समाज विकसित होगा, जहां शिक्षा केवल जानकारी प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि समाज के निर्माण और विकास का माध्यम बनेगी। यह बदलाव भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। भारत का भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर है। यह नई शिक्षा नीति भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और वैश्विक दृष्टिकोण वाला देश बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।"[4]

समाजिक समरसता बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने, सकारात्मक सोच को विकसित करने, महिलाओं में चेतना जाग्रत कर उन्हें सशक्त बनाने, युवाओं को रोजगारोन्मुखी ज्ञान प्रदान करने, कृषि, चिकित्सा, अन्तरिक्ष, रक्षा आदि विभिन्न क्षेत्रों में नित-नूतन होने वाले परिवर्तनों की जानकारी देने का कार्य शिक्षा एवं शिक्षकों द्वारा किया जाता है। जो भारत को समृद्ध, उन्नत और विकसित बनाने में सहायक है।

भारत को विकसित बनाने के लिए देश में विश्व स्तरीय शिक्षा की जरूरत है इस सन्दर्भ में निति आयोग में भी एक

पॉलिसी रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग ने 'राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के जरिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार' शीर्षक से एक पॉलिसी रिपोर्ट जारी की है। यह उच्च शिक्षा क्षेत्र में अपनी तरह का पहला नीति दस्तावेज है, जो खासकर राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों (एसपीयू) पर केंद्रित है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश में विश्व स्तरीय शिक्षा के जरूरत होगी। यह रिपोर्ट सोमवार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीति आयोग में सदस्य (शिक्षा) डॉ. विनोद कुमार पॉल, नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम, उच्च शिक्षा विभाग सचिव विनीत जोशी और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) महासचिव डॉ. पंकज मित्तल द्वारा जारी की गई।

यह पिछले दशक में विभिन्न विषयों पर गुणवत्ता, वित्तपोषण, प्रशासन और रोजगार के महत्वपूर्ण संकेतकों पर विस्तार से परिमाणात्मक विश्लेषण प्रदान करता है। रिपोर्ट 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभागों के राज्य सरकार के अधिकारियों, कुलपतियों और 50 एसपीयू के वरिष्ठ शिक्षाविदों और कई राज्य उच्च शिक्षा परिषदों के अध्यक्षों के साथ आयोजित व्यापक चर्चाओं के मिली विशेष जानकारियां मुहैया कराती है। एसपीयू को भी उच्च मानकों के लिए कोशिशें करनी चाहिए।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि कई वैश्विक शिक्षा प्रणालियों में, सार्वजनिक विश्वविद्यालय उत्कृष्टता के मानक स्थापित करते हैं, जैसा कि अमेरिका और ब्राजील में देखा गया है। भारत में चूंकि आईआईटी जैसे संस्थान हैं, एसपीयू को भी उच्च मानकों के लिए कोशिशें करनी चाहिए। रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों को केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालय उत्साहपूर्वक आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार, नीति आयोग की भूमिका शोध के जरिए साक्ष्य तैयार करना है, जबकि कार्यान्वयन मंत्रालय की जिम्मेदारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों को केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालय उत्साहपूर्वक आगे बढ़ाएंगे। एसपीयू में सुधार करना बेहद जरूरी है।

वहीं, नीति आयोग के सदस्य डॉ. विनोद कुमार पॉल ने रिपोर्ट को एनईपी के कार्यान्वयन और विकसित भारत 2047 के लिए भारत के दृष्टिकोण के संदर्भ में रखा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि भारत की 80 प्रतिशत उच्च शिक्षा एसपीयू में प्राप्त हो रही है, मानव पूंजी बनाने और भारत को एक ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए उनमें सुधार करना बेहद जरूरी हो जाता है। उच्च शिक्षा प्रणाली में छात्रों का नामांकन को करीब 9 करोड़ तक पहुंचाना है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने जोर देते हुए कहा कि 2035 तक, एनईपी 2020 का लक्ष्य, उच्च शिक्षा प्रणाली में छात्रों का नामांकन दोगुना करते हुए इसे करीब 9 करोड़ तक पहुंचाना है। इनमें से लगभग 7 करोड़ एसपीयू में पढ़ाई जारी रखेंगे। इसलिए, यह बेहद जरूरी है कि ये विश्वविद्यालय केवल उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाने पर ध्यान केंद्रित ना करते हुए, 2047 तक विकसित भारत बनने के दृष्टिकोण को मजबूती देने के लिए जरूरी उच्च गुणवत्ता वाले मानव संसाधन तैयार करने के लिए भी विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान करने पर जोर दें। उन्होंने रिपोर्ट को नीति आयोग की बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया, जो भारत के उच्च शिक्षा के परिदृश्य को बदलने में एनईपी 2020 का पूरक होगी।[5]

विकसित भारत 2047 की ओर शिक्षा की परिवर्तनकारी यात्रा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें अकादमिक उत्कृष्टता के साथ-साथ नैतिकता और नैतिक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। तेजी से हो रहे वैश्विक परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों के लिए ज्ञान अन्तराल को पाटने और अन्तःविषय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता है। समकालीन मुद्दों को प्रभावी ढंग से सम्बोधित करने के लिए छात्रों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करना और स्चनात्मकता को विकसित करना अनिवार्य है।

शिक्षा प्रणाली में वास्तविक जीवन के अनुभवों को एकीकृत करने और आलोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। शिक्षा में विविधता और समावेशिता को अपनाने से समाज का ताना-बाना मजबूत होगा और राष्ट्रीय विकास के लाभों में योगदान मिलेगा। इससे अलावा, कम लागत वाले वेबिनार और मास मीडिया जुड़ाव जैसी पहल शिक्षा के प्रभाव को बढ़ा सकती हैं, युवाओं में सामाजिक जागरूकता और नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा दे सकती है। जटिल सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्यों से गुजरते हुए, नवाचार और प्रगति को अपनाते हुए पारम्परिक

मूल्यों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, नैतिक स्पष्टता और व्यावहारिक कौशल से लैस एक पीढ़ी का पोषण करके, हम भारत और दुनिया के लिए एक उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते है।

विकसित भारत 2047 की ओर यात्रा के लिए शिक्षकों, नीति निर्माताओं और बड़े पैमाने पर समाज के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। नैतिक शिक्षा को प्राथमिकता देकर, अंतःविषय सीखने को बढ़ावा देकर और विविधता को अपनाकर, हम एक समृद्ध और समावेशी भविष्य के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण कर सकते है।[6] 2047 तक, भारत स्वतन्त्रता के 100 वर्ष मनाएगा। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करनी चाहिए जो सभी भारतीयों को सशक्त बनाए, समावेशी विकास को बढ़ावा दें और उन्हें 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करे।

सुझाव

2047 तक एक गतिशील और सशक्त भारत को आकार देने में उनके सामूहिक योगदान को निर्धारित करने के लिए शिक्षा के विभिन्न पहलुओं की व्यापक जांच की जानी चाहिए।[7] शिक्षक विद्या का वाहक होता है। देश के भविष्य का निर्माता होता है। विद्यार्थी की सोच का निर्माण शिक्षक ही करता है। इसलिए विकसित भारत 2047 में शिक्षक की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। वह नूतनता के प्रवाह को समझकर, विद्यार्थी को उसके अनुरूप ढाल सकता है। शिक्षक विद्यार्थी को जड़ों से जुड़े रहकर आधुनिकता को अपनाने का ज्ञान दे सकता है, जो भारत को विकसित बनाने में मददगार होगा।

समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को, उनकी क्षमताओं या पृष्ठभूमि से परे, एक साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इसमें शिक्षक की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक को एक ऐसा वातावरण बनाना होता है जहाँ सभी बच्चे सुरक्षित और स्वीकृत महसूस करें। उन्हें प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पहचानना और उनके अनुसार शिक्षक विधियों को अपनाना होता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, शिक्षक को व्यक्तिगत शिक्षा योजना तैयार करनी चाहिए और सहायक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। पाठ्यक्रम को इस तरह से अनुकूलित किया जाना चाहिए कि वह सभी बच्चों के लिए सुलभ हो। इसके लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण और संसाधनों की आवश्यकता होती है।

शिक्षक एक ऐसा स्तंभ है, जिसके बिना समाज और राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। वे न केवल बच्चों को शिक्षित करते हैं, बल्कि उन्हें समाज का जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा को मार्गदर्शन भी करते हैं हालांकि, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनसे निपटने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। यदि शिक्षक प्रभावशीलता को बढ़ाने और उनकी चुनौतियों को दूर करने के लिए समुचित कदम उठाए जाएँ तो निः सन्देह, शिक्षा की गुणवता में सुधार होगा और हमारा देश समृद्ध और शक्तिशाली बनेगा।[8]

भारत को विकसित बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक ज्ञानवान हो और शीलवान हो। विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में सहायक हों। क्योंकि चरित्रवान विद्यार्थी ही देश को भ्रष्टाचार मुक्त परिवेश प्रदान कर सकेगा जिससे भारत विकसित बनेगा। शिक्षक सही दिशा देने में और सकारात्मक सोच विकसित करने में भी भूमिका निभा सकता है। शिक्षक को नवाचार करते रहना चाहिए और समय के साथ गतिशीलता को भी बनाए रखना चाहिए। आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के युग में शिक्षक को डिजिटीलाईजेशन के साथ आगे बढ़ना होगा तथा नवीनतम तकनीक को जानना और समझना जरूरी होगा। तभी भारत 2047 में विकसित बन पाएगा। अब शिक्षक को केवल शिक्षक नहीं गुरु बनना जरूरी है।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शिक्षा एवं शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष

विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब समग्र विकास के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक में नैतिकता, चारित्रिक बल एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश हो। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, जी.डी.पी. में निरंतर वृद्धि, सामाजिक समरसता, स्वच्छ पर्यावरण, तकनीकी उन्नति, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगति, तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठा—ये सभी तत्व विकसित भारत की संकल्पना को सशक्त बनाते हैं।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने में शिक्षा और शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षक न केवल ज्ञान का संप्रेषण करते हैं, बल्कि वे भावी पीढ़ी के नैतिक और चारित्रिक निर्माण के शिल्पकार भी हैं। शिक्षा को सार्वभौमिक, सर्वसमावेशी एवं व्यावहारिक बनाते हुए शिक्षक विद्यार्थियों में विश्लेषणात्मक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नागरिक शिष्टाचार और स्वदेशी चेतना को विकसित कर सकते हैं। शिक्षक स्वयं एक आदर्श बनें और विद्यार्थियों के जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं।

इस प्रकार, यदि भारत का प्रत्येक शिक्षक अपनी भूमिका को राष्ट्र निर्माता के रूप में समझे, तो विकसित भारत की परिकल्पना न केवल संभव, बल्कि शीघ्र साकार भी हो सकती है।

सन्दर्भ सूची

1. गुप्ता, अंकित, क्या है पी.एम.मोदी का 'विकसित भारत 2047' मिशन, कैसे पूरा होगा सपना?, टीवी9हिन्दी.कॉम 15 अगस्त, 2024
2. कुमार, आलोक, वितमंत्री निर्मला सीतारमण ने 'विकसित भारत' का खाका साझा किया। इंडिया टी.वी., 23 अक्तूबर, 2024
3. विकसित भारत 2047 : विजन ऑफ न्यू इंडिया 3.0, कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति के सम्बोधन का मूल पाठ (अंश), 30 नवम्बर 2024,पी.आई.बी दिल्ली (उपराष्ट्रपति सचिवालय)
4. पन्त जी.बी., विकसित भारत मिशन का आधार बनेगा 2025 का शिक्षा मॉडल, प्रो. बद्रीनारायण तिवारी, निदेशक, सामाजिक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद / पत्रिका. कॉम, राजस्थान पत्रिका, 1 जनवरी 2025, पृ.सं. 4
5. 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए में विश्व स्तरीय शिक्षा की जरूरत : नीति आयोग डीडी न्यूज.जीओवी.इन 11.02.2025
6. हिन्दवान, सुधीर, विकसित भारत को आकार देने में शिक्षा की भूमिका, बुधवार, 10 अप्रैल, 2024, द पाईओनीयर
7. विकसित भारत के विचार-2047 में शिक्षा, राजीव रंजन, 01 जनवरी, 2024 लिंक्ड इन. कॉम
8. मंसूर, अब्दुल्लाह, राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका : चुनौतियाँ और समाधान, 07 सित. 2024, पसमन्दा डेमोक्रेसी